दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **5**

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 5
- सालगाँव बाँध परियोजना 5
- निर्यातक बनो मिशन 6
- घुश्मेश्वर गाथा (Ghushmeshwar Gatha) 6
- घर-घर औषधी योजना (Ghar Ghar Aushadhi Yojana) 7
- अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन (Early Cancer Detection Van) 7
- कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति 8
- बा-बापू अमृत महोत्सव वृक्षारोपण अभियान 8
- 'खेल साक्षरता मिशन' 8
- 66वीं राजस्थान राज्य सीनियर टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 9

नोट :

- बॉयोफ्यूल आउटलेट आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ 9
- जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) 9
- महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 10
- भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक 10
- 'गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक' 2021 11
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Divyangjan Rights Act) 11
- केंद्रीय जेल में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम (Tree Plantation in Central Jail) 12
- सिलीसेढ़ तिराहा-गरवाजी सड़क 12
- 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' के प्रारूप का अनुमोदन 12
- 15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण एवं 9 थानों का शुभारंभ 13
- पुष्कर एवं जैसलमेर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित 14
- कोटा ज़िले में नवीन कार्यों का लोकार्पण 14
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल 14
- 11 ज़िलों के 85 गाँव अभावग्रस्त घोषित 15

नोट :

- राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच समझौता 15
- 'आइडिया वॉल' 16
- 'हर घर नल कनेक्शन' 16
- MyBookLo ऐप 17
- नाथद्वारा में हेलिकॉप्टर जॉयराइड 17
- पैरालंपिक में स्वर्णिम सफलता 18
- टोक्यो पैरालंपिक खेल में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिये पुरस्कार 18

दृष्टि The Vision

नोट :

राजस्थान

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021

चर्चा में क्यों ?

- 27 जुलाई, 2021 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने व सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत सामूहिक विवाह के आयोजन, आवेदन एवं भुगतान का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों एवं आयोजनकर्त्ता संस्थानों को अधिक-से-अधिक लाभ देना है।
- इस योजना में विवाह आयोजन की अनुमति के लिये विवाह की तिथि से कम-से-कम 15 दिन पहले ऑफलाइन आवेदन के स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है।
- विवाह पंजीयन हेतु समयावधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गई है।
- वधुओं द्वारा बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गई है।
- सामूहिक विवाह के आयोजन दिन IFMS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से 10 हज़ार रुपए का हस्तांतरण वधू के खाते में तथा 3 हज़ार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाएगा।
- विवाह आयोजन के पश्चात् 60 दिन की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर 5 हज़ार रुपए की राशि का हस्तांतरण वधू के खाते में किया जाएगा।
- प्रकरण में आने वाली समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर द्वारा प्रावधान किया गया है।

सालगाँव बाँध परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- 28 जुलाई, 2021 को लंबे समय से प्रस्तावित माउंट आबू की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु 'सालगाँव बाँध परियोजना' (Salgaon Dam Project) के लिये उक्त परियोजना की नीति निर्धारण समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- सालगाँव बाँध परियोजना 44 साल पहले 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनना प्रस्तावित थी जबकि वर्तमान में इस परियोजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए है।
- सालगाँव बाँध परियोजना, माउंट आबू की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है।
- चूँकि माउंट आबू अपनी जल आपूर्ति के लिये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है, इसलिये राजस्थान सरकार ने वर्षा जल भंडारण की सुविधा के लिये सालगाँव बाँध योजना को बहुत पहले मंज़ूरी दे दी थी।
- इस परियोजना में सालगाँव बाँध का कुल जलग्रहण क्षेत्र 777.90 हेक्टेयर है और कुल भराव क्षमता अनुमानत: 155.56 मिलियन घनपुट है।
- बाँध का कुल डूब क्षेत्र 52.55 हेक्टेयर है, जिसमें से 5.96 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि है तथा 46.59 हेक्टेयर निजी एवं सरकारी भूमि है।
- उल्लेखनीय है कि माउंट आबू की वर्तमान जल परियोजनाओं में पेयजल का मुख्य स्रोत अपर कोदरा एवं लोवर कोदरा है, जिससे प्रतिवर्ष करीब 42.62 मिलियन क्यूबिक फीट (MCFT) जल उपलब्ध होता है, जबकि माउंट आबू की वर्तमान जल मांग 85.21 MCFT (स्कूल, आर्मी, टूरिस्ट की आबादी को सम्मिलित करते हुए) आँकी गई है।

नोट :

निर्यातक बनो मिशन

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2021 को राजस्थान में उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा द्वारा 'निर्यातक बनो' (Be an Exporter) मिशन की शुरुआत की गई।
  - गौरतलब है कि एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2020 में राजस्थान स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहले और संपूर्ण देश में चौथे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन के बारे में
  - इस मिशन के तहत ऐसे व्यापारी एवं उत्पाद निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो निर्यात के इच्छुक हैं और अपने उत्पादों को विदेशी बाज़ार तक पहुँचाना चाहते हैं।
  - उद्योग विभाग द्वारा संचालित इस मिशन में निर्यात के इच्छुक उम्मीदवार को न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने में आने वाली सभी तकनीकी परेशानियों का समाधान कर उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
  - इस योजना से जुड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्यात लाइसेंस दिलवाने की प्रक्रिया से लेकर पहला कंसाइनमेंट भेजने तक विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा।
  - इस अभियान के माध्यम से राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद (REPC) के तहत पंजीकरण और सदस्यता शुल्क में छूट भी दी जाएगी।
- आवश्यकता
  - राज्य में निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए एवं राज्य में इच्छुक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है।
- योग्यता
  - इस मिशन के तहत स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली फर्म एवं MSME तथा किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता एवं खुदरा व्यापारी, राज्य में कार्यरत स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स से जुड़े व्यक्ति निर्यातक बन सकते हैं।

घुश्मेश्वर गाथा (Ghushmeshwar Gatha)

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र को राज भवन में 'घुश्मेश्वर गाथा' की प्रथम प्रति भेंट की गई।

प्रमुख बिंदु

- शिवाड़ समाज जयपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर हैं।
- 'घुश्मेश्वर गाथा' में भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता रखने वाले सवाई माधोपुर ज़िले में शिवाड़ स्थित पावन तीर्थ स्थल घुश्मेश्वर महादेव की प्राचीनता, यहाँ मिले असंख्य शिवलिंगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
- पुस्तक में शिवाड़ के पौराणिक, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही यहाँ से जुड़ी अलौकिक घटनाओं और आस-पास के दर्शनीय स्थलों की विशद जानकारी दी गई है।
- धार्मिक और ऐतिहासिक महत्त्व की इस पुस्तक में घुश्मेश्वर मंदिर में राजाओं के दौर में बनाए अन्य मंदिरों, तालाबों, कुएँ-बावड़ियों और इतिहास से जुड़े अनछुए पहलुओं की महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं।

नोट :

घर-घर औषधी योजना (Ghar Ghar Aushadhi Yojana)

चर्चा में क्यों ?

- 01 अगस्त, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'निरोगी राजस्थान अभियान' (Nirogi Rajasthan Campaign) के तहत 'घर-घर औषधी योजना' तथा 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर गिलोय का औषधीय पौधा लगाकर योजना की शुरुआत की। साथ ही 72वें वन महोत्सव के तहत जयपुर के ग्राम बिलौंची में लगाने के लिए पीपल का पौधा और अन्य पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इस अवसर पर औषधीय पौधों की पहली किट वन राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को भेंट की। गहलोत ने 'घर-घर औषधी योजना' के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किये गए पोस्टर, ब्रोशर एवं बुकलेट का विमोचन भी किया।
- राजस्थान संभवत: पहला प्रदेश है, जिसने औषधीय पौधों के प्रति जनचेतना जागृत करने के लिए वृहद स्तर पर ऐसी अनूठी योजना लागू की है।
- उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य रक्षण तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को पाँच वर्ष में तीन बार आठ-आठ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- गौरतलब है कि निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए भावी पीढ़ी को इन औषधीय पौधों के महत्त्व और उपयोग की जानकारी दिलाने हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 'घर-घर औषधीय योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।

अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन (Early Cancer Detection Van)

चर्चा में क्यों ?

- 3 अगस्त, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने अपने राजकीय आवास से अर्ली कैंसर डिटेक्शन (प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी मोबाइल) वैन [(Early Cancer Detection (Preventive Oncology Mobile) Van)] का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन जुड़ी यह वैन प्रदेश के सुदूर गाँवों में जाकर मरीज़ों की जाँच करेगी और रिपोर्ट भी उसी समय उपलब्ध कराएगी।
- इस वैन में मेमोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स-रे, कोलपोस्कॉपी, पैप स्मियर तथा सिर और गर्दन के परीक्षण के लिये वीडियो एंडोस्कॉपी की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- लगभग 1.25 करोड़ रुपए लागत की यह वैन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड के सीएसआर फंड से प्राप्त हुई है।
- डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि लक्षणों को जल्द पहचानने में यह वैन खासी कारगर होगी। अर्ली डिटेक्शन से 90 प्रतिशत से अधिक कैंसर रोगियों का पूर्ण उपचार संभव है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक कोई प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी यूनिट नहीं थी। इस वैन से टेली कंसल्टेंसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जनता के स्वास्थ्य पर रिसर्च डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

नोट :

कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति

चर्चा में क्यों ?

- 05 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति (Committee to Examine the Demands of Employees and Officers) के गठन को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- यह समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसरों, एसीपी, भत्तों की निरंतरता एवं उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वित्तीय भार इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों, यथा- पटवारी, मंत्रालयिक एवं कॉन्स्टेबल आदि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करेगी।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद पांड्या समिति के सदस्य एवं संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) सदस्य सचिव होंगे।
- उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की मांगों के संबंध में उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी।

बा-बापू अमृत महोत्सव वृक्षारोपण अभियान

चर्चा में क्यों ?

- 6 अगस्त, 2021 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर की ग्राम पंचायत लाठी में बा-बापू वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी के प्रांगण में पौधारोपण कर इसका शुभारंभ किया।
- इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत लाठी में तैयार होने वाले सेवण चारागाह घास विकास कार्य का भी शुभारंभ किया।
- ध्यातव्य है कि राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती वर्ष एवं आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बा-बापू वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है।

'खेल साक्षरता मिशन'

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता और इससे नई पीढ़ी को जोड़ने के लिये चलाए गए 'खेल साक्षरता मिशन' चल वाहन का राजभवन में अवलोकन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह वाहन विभिन्न राज्यों से होता हुआ सोमवार को जयपुर पहुँचकर नई दिल्ली के लिये रवाना हुआ।
- राज्यपाल मिश्र ने देशभर में 'स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ'के अंतर्गत इस वाहन के जरिये ओलंपिक खेलों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने और इनके बारे में जागरूकता के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

नोट :

- स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ'संस्था द्वारा खेलों से जुड़ी शब्दावली, खेल संस्कृति और विभिन्न खेलों के बारे में बनायी गयी 'खेल प्रवेशिका' के जरिये ओलंपिक खेलों के बारे में जागरूकता प्रयासों की भी उन्होंने तारीफ की।
- राज्यपाल मिश्र ने कहा कि खेल संस्कृति का विकास सभी स्तरों पर होना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ने और इसके लिये सभी स्तरों पर प्रोत्साहन दिये जाने के लिये ऐसे प्रयासों को महत्त्वपूर्ण बताया।

66वीं राजस्थान राज्य सीनियर टेबिल टेनिस प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

- राजस्थान में अजमेर के मूलचंद चौहान इंडोर स्टेडियम में सात व आठ अगस्त को 66वीं राजस्थान राज्य सीनियर टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में जयपुर की नंदिनी नागौरी ने अजमेर की राधिका शर्मा को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल में अजमेर के हर्ष श्रीवास्तव ने जयपुर के विवेक भार्गव को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीता।
- दो दिवसीय प्रतियोगिता में जोधपुर, सिरोही, पाली, अलवर, बीकानेर, जयपुर, चुरू, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालौर, उदयपुर, गंगानगर, भरतपुर, दौसा व आयोजक अजमेर ज़िले के कुल 86 प्रतिस्पर्द्धियों ने लगभग 25 हज़ार रुपये की प्राइजमनी वाली प्रतियोगिता में अपने पैडल्स के कौशल का परिचय दिया।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय टेबिल टेनिस संघ तथा राजस्थान टेबिल टेनिस संघ देश व राज्य के उन चुनिंदा खेल संघों में से हैं, जिन्होंने सत्र 2020 तथा सत्र 2021 के भीषण वैश्विक महामारी के दौर में भी खिलाड़ियों व खेल के उत्साहवर्द्धक के लिय एसओपी का निर्वाहन करते हुए समस्त राज्य व राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएँ संपन्न करवाई।

बॉयोफ्यूल आउटलेट आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 10 अगस्त, 2021 को राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. के.के. पाठक ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में बॉयोफ्यूल स्टेकहोल्डर्स हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑनलाइन पोर्टल के शुरू हो जाने से बॉयोफ्यूल उत्पादक, आपूर्तिकर्त्ता व रिटेल आउटलेट आवेदन हेतु आमजन के लिये पंजीयन प्रक्रिया सरल, सुलभ, पारदर्शी हो सकेगी एवं पंजीयन कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण हो सकेगा।
- डॉ. पाठक ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आउटलेट आवेदन हेतु अब आवेदकों को जयपुर नहीं आना पड़ेगा, इससे उनके समय व धन की बचत होगी।
- राजस्थान राज्य बॉयोफ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्राधिकरण की वेबसाइट www.biofuel.rajasthan.gov.in पर जाकर राज्य के किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)

चर्चा में क्यों ?

- 10 अगस्त, 2021 को राजस्थान के जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में आरडब्ल्यूएसएसएमबी की नीति निर्धारण समिति (पीपीसी) की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चार हज़ार से अधिक गाँवों में हर घर नल कनेक्शन को मंजूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वृहद पेयजल परियोजनाओं तथा वृहद पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की योजनाओं में 4 हज़ार 163 गाँवों की 62 योजनाओं में 7 लाख 70 हज़ार 395 हर घर नल कनेक्शन देने के एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
- इन पर 5056 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। वृहद पेयजल परियोजनाओं के तहत 4,718 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 21 योजनाओं को स्वीकृति दी गई, इनमें 2 हज़ार 815 गाँवों में 7 लाख 10 हज़ार 169 हर घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- इसी प्रकार वृहद पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि की योजनाओं में 41 सिंगल एवं मल्टी विलेज ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव मंजूर किये गए, इनमें 1348 गाँवों में 60 हजार 226 हर घर नल कनेक्शन होंगे, जिन पर 338 करोड़ रुपए से अधिक व्यय होंगे।
- जलदाय मंत्री ने बैठक में अतिरिक्त एजेंडा प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। इनमें मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत हरमाड़ा-भडारना को जयपुर शहरी जलप्रदाय योजना के तहत बीसलपुर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिये 43.48 करोड़ रुपए तथा बाड़ी (धौलपुर) में पेयजल आपूर्ति योजना के लिये 38.85 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
- इसके अलावा प्रदेश में जेजेएम की योजनाओं के तहत वर्ष 2021-2022 में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस प्लान के तहत 67.81 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में जलदाय विभाग की प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन, फील्ड टेस्टिंग किट खरीदने तथा पेयजल गुणवत्ता जाँच के लिये क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों का संचालन होगा।
- सवाई माधोपुर में मोरल नदी पर एनीकट निर्माण पर 16.26 करोड़ तथा बीसलपुर प्रोजेक्ट में सूरजपुरा से सांभर तक 539 गाँवों में पेयजल आपूर्ति के लिये ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइन के लिये 265.96 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज

चर्चा में क्यों ?

- 11 अगस्त, 2021 को राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में सेंट्रल पार्क स्थित कनक भवन में आगामी 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना करने एवं यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन शुरू कराने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- यह संस्थान मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में 100 करोड़ रुपए की लागत से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की तर्ज़ पर शुरू किया जा रहा है।
- इस संस्थान को बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है।
- यह इंस्टीट्यूट युवाओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के लिये तैयार करने में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
- इस संस्थान का उद्देश्य महात्मा गांधी के जीवन तथा सामाजिक मूल्यों के दर्शन को शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से समाज के हर तबके तक पहुँचाना है।

भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 11 अगस्त, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओ.पी. बुनकर की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के सभागार में जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक हुई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बैठक में अतिरिक्त निदेशक-सामाजिक सुरक्षा सुवालाल पहाड़िया ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, 18 से 55 वर्ष तक की आयु के महिला व पुरुष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं अशक्त और दिव्यांग लोगों के हिसाब से श्रेणीवार भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का चिह्नीकरण किया गया है।
- इसके लिये शहर में 25 पॉइंट चिह्नित किये गए हैं, जहाँ भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति मिलते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऐसे चिह्नित स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का विवरण एक प्रारूप में दर्ज किया जाएगा, उसके पश्चात् उनकी काउंसलिंग कर उन्हें निराश्रित बाल गृह, महिला सदन, वृद्धाश्रम तथा आवश्यकतानुसार विकलांग पुनर्वास गृहों में प्रवेश दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि अभियान में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के युवा वर्ग को लक्ष्य वर्ग के रूप में लिया गया है। जो भी युवा भिक्षावृत्ति में लिप्त हो तथा वह कोई कार्य करना चाहता हो अथवा वह किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे, उसे उसकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिलाकर पुनर्वासित किया जाना इस अभियान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

'गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक' 2021

चर्चा में क्यों ?

- 12 अगस्त, 2021 को राजस्थान के उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार सहित प्रदेश के 9 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिये 'गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पद' प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस पदक की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अपराधों की जाँच में उच्च प्रोपेशनल मानकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट अन्वेषण करने वाले जाँच अधिकारियों की मेहनत को पहचान देना है।
- उल्लेखनीय है कि 'गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक' प्राप्त करने वाले अनंत कुमार राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों से जुड़े 12 आतंकियों की जाँच के केस में राजस्थान एटीएस के तत्कालीन जाँच अधिकारी रहे थे। दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च, 2014 को एफआईआर दर्ज करके इन आतंकियों की जाँच शुरू की थी।
- अनंत कुमार और उनकी टीम ने उच्च प्रोफेशनल मानकों को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट अन्वेषण किया तथा उन 12 आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी पायी। इस मामले में उन 12 आतंकियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा हुई थी।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के साथ डिप्टी एसपी सुरेश शर्मा, इंस्पेक्टर अनिल डोरिया, इंस्पेक्टर दिनेश लखावत, इंस्पेक्टर दरज्या राम, इंस्पेक्टर अशोक आंजना, डीसीपी धर्मेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर अरुण कुमार, हेड कॉन्स्टेबल भवानी सिंह को भी गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक 2021 प्रदान किया गया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Divyangjan Rights Act)

चर्चा में क्यों ?

- 13 अगस्त, 2021 को राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Divyangjan Rights Act) को लागू किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिव्यांगजन व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना, दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना आदि का प्रावधान किया गया है।

नोट :

- इसी प्रकार दिव्यांगता के आधार पर उन्हें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए इसका प्रावधान भी अधिनियम में शामिल है।
- राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने, दिव्यांगजन व्यक्तियों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से बचाने हेतु उपाय एवं प्रावधान किये गए हैं।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग द्वारा अधिनियम की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित निकाय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

केंद्रीय जेल में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम (Tree Plantation in Central Jail)

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कारागृह जयपुर में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय के अध्यक्ष रणधीर सिंह मिर्धा द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उक्त कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय कारागृह जयपुर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण द्वारा 300 पौधे (छायादार एवं फलदार) लगाये गये।
- इसी प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय न्याय क्षेत्र आमेर व चौमू में भी सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ चौमू न्यायालय में 110 पौधे एवं आमेर न्यायालय में 55 पौधे लगाये गये।
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने बताया गया कि यह कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

सिलीसेढ़ तिराहा-गरवाजी सड़क

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में 840 लाख रुपए की लागत से 14 किमी. लंबाई की बनने वाली सिलीसेढ़-गरवाजी सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि सिलीसेढ़ झील एवं गरवाजी ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और यहाँ सड़क बनने से आवागमन में सुविधा होगी।
- राज्य मंत्री ने इस सड़क पर रोड लाइट लगवाने और सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण करवाने की बात भी कही। इससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे और पर्यटन क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
- इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर आमजन की सुविधा के लिये सिलीसेढ़ तिराहे पर सिंगल पेस बोरिंग कराने और सिलीसेढ़ क्षेत्र के दूरस्थ गाँवों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की घोषणा भी की।

'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' के प्रारूप का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोज़गारों को स्वरोज़गार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिये 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021' के प्रारूप का अनुमोदन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री गहलोत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोज़गार, स्वरोज़गार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस वर्ष के बजट में 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' लागू करने की घोषणा की थी।
- योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई-पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिये आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
- इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हज़ार रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों के लिये अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- योजना एक वर्ष के लिये लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिये ज़िला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।

15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण एवं 9 थानों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 15 पुलिस थानों के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित 9 पुलिस थानों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने जयपुर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में एक-एक, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा एवं नागौर में 3 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा जयपुर पूर्व और डूंगरपुर में 2, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक नए थाने का शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी हो। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर नए थाने स्थापित करने के साथ ही पुलिस चौकियों को भी थानों में क्रमोन्नत किया जा रहा है, ताकि लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिये दूर नहीं जाना पड़े।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और ज़िला स्तर पर गंभीर एवं जघन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है।
- पुलिस थानों, प्रशासनिक भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, थानों में सीसीटीएनएस कक्ष, साइबर कक्ष, पुलिस अनुसंधान कक्ष, महिला बैरक, रेस्ट रूम, स्वागत कक्ष आदि का निर्माण किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्मित पुलिस थानों- हनुमानगढ़ सदर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) तथा महिला पुलिस थाना (नागौर) में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों-कार्मिकों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर आदि से संवाद भी किया।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की उचित माहौल में सुनवाई के लिये थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण का नवाचार किया है। करीब 454 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है।
- प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये प्रदेश में विगत ढाई वर्ष में एक पुलिस ज़िला, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 21 थानों, 2 साइबर थानों, 32 चौकियों, 2 एटीएस की चौकियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लिये एसओजी की 2 फील्ड यूनिट एवं एक एंटी नार्कोटिक इकाई का गठन किया गया है। साथ ही, 2422 हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को माइनर अनुसंधान के अधिकार दिये गए हैं।

नोट :

पुष्कर एवं जैसलमेर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि पुष्कर एवं जैसलमेर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर दोनों शहरों की विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री ने सचिवालय में अक्षय ऊर्जा परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
- उन्होंने कहा कि शहरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहनों आदि का संचालन कर परंपरागत तरीकों से प्राप्त विद्युत की निर्भरता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु, आरआरईसी केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करेगी।

कोटा ज़िले में नवीन कार्यों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 20 अगस्त, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा ज़िले को चिकित्सा के क्षेत्र में नई सौगात देते हुए 16.53 करोड़ रुपए के नवीन कार्यों का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने निम्नलिखित कार्यों का लोकार्पण किया-
  - मेडिकल कॉलेज में 525 लाख रुपए की लागत की नवनिर्मित एमडीआरयू लैब का लोकार्पण किया, इस पर 47.44 लाख रुपए एक वर्ष के संचालन पर व्यय होंगे।
  - 99.75 लाख रुपए लागत की 3 जीवन रक्षक उपकरण युक्त एम्बुलेंस विथ नेगेटिव प्रेशर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
  - मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही 800 लाख की लागत से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में नवनिर्मित किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण किया।
  - सुपर स्पेशयलिटी चिकित्सालय में 115.94 लाख की लागत से निर्मित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण कर पौधारोपण भी किया।
  - जेके लोन अस्पताल में 65 लाख रुपए की लागत से नवस्थापित 4-डी कलर डॉप्लर सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। इससे गर्भ में पल रहे शिशु की विशेष रूप से जन्मजात अंगों की कुरुपता की जाँच की जा सकेगी, महिलाओं एवं शिशु से संबंधित रोगों के निदान में सुविधा होगी तथा इससे माँसपेशियों एवं जोड़ों की सोनोग्राफी भी कराई जा सकेगी।
- शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा में अब एसएमएस अस्पताल जयपुर के समान चिकित्सा सुविधाएँ मिलने लगेंगी। इससे संपूर्ण हाड़ौती सहित मध्य प्रदेश राज्य से आने वाले रोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
- डॉ. शर्मा ने कहा कि कोटा में शिशु मृत्यु दर के मामलों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण कमी आई है। 2014 में मृत्यु दर 7.62 प्रतिशत थी, जो 2020 में 6.84 प्रतिशत रही तथा नवजात शिशु मृत्यु दर 19 प्रतिशत से घटकर 17.63 प्रतिशत रह गई है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

- 25 अगस्त, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत देय सहायता राशि का त्वरित एवं ऑनलाइन भुगतान करने हेतु केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अब तक कोरोना महामारी से चिह्नित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को ज़िला कलेक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही किया जाता था। अब विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित बच्चों एवं विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति एवं सीधे ही उनके बैंक खाते के माध्यम से नियमित भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल विकसित किया गया है।
- अब विभाग द्वारा ऑफलाइन भुगतान किये गए समस्त लाभार्थियों को पोर्टल पर फीड कर मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त एवं मासिक देय सहायता राशि का निरंतर निदेशालय स्तर से राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (आरपीपी) के माध्यम से केंद्रीकृत भुगतान समय पर किया जाएगा।
- इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी। राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरित होने का एसएमएस भी पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है।

11 ज़िलों के 85 गाँव अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 25 अगस्त, को 2021 राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि से खराब होने की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 11 ज़िलों के 85 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने बताया कि अलवर ज़िले का एक, बाड़मेर के 2, बीकानेर के 4, भरतपुर के 9, चित्तौड़गढ़ के 2, चूरू के 2, हनुमानगढ़ के 19, झुंझुनूं के 28, कोटा के 8, सवाई माधोपुर के 6 एवं टोंक ज़िले के 4 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, कोटा, सवाई माधोपुर तथा टोंक से प्राप्त रबी फसल 2020-21 में ओलावृष्टि से खराब होने की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ज़िलों के 85 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
- यह प्रावधान ऐसे प्रभावित गाँवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

- 26 अगस्त, 2021 को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 1,200 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद हेतु निविदा में आई दर पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पवन ऊर्जा आगामी डेढ़ वर्ष (18 महीने) में राज्य को उपलब्ध हो जाएगी।
- उन्होंने कहा कि एसईसीआई ने दिसंबर 2020 में राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिये 1,200 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीदने हेतु पवन ऊर्जा उत्पादन कंपनियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
- राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के फलस्वरूप ऊर्जा विभाग को निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार, विभाग को 300 मेगावाट के लिये 2.77 रुपए प्रति यूनिट और 900 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिये 2.78 रुपए प्रति यूनिट की न्यूनतम बोली प्राप्त हुई, जो 2020-21 में राज्य की औसत बिजली खरीद लागत 4.61 रुपए प्रति यूनिट से काफी कम है।

नोट :

- इन परियोजनाओं के चालू होने पर राज्य की औसत क्रय दर में और कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
- गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में गैर-पारंपरिक स्रोतों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की थी। गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने और राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में एक नवीनीकृत सौर एवं पवन ऊर्जा नीति भी जारी की थी।

'आइडिया वॉल'

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्मित 'आइडिया वॉल' पर हस्ताक्षर किये। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्पित रहते हुए सशक्त, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा 'आइडिया वॉल' निर्मित किये जाने के साथ ही आज़ादी आंदोलन से जुड़े सेनानियों और घटनाओं पर केंद्रित 15 स्टैंड मिनी मोबाइल प्रदर्शनी की पहल की गई।
- 'आइडिया वॉल' पर प्रदेश के 75 गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नए भारत के निर्माण के लिये विचार और सुझाव लिखे जाने की राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुरुआत की।
- प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला और अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने इस अवसर पर बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'आइडिया वॉल' पर गणमान्य व्यक्तियों के विचार और सुझाव एकत्र कर 75 चुनिंदा सुझाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजे जाएंगे।
- इसी के साथ राज्यपाल ने कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से राजभवन से मोबाइल एक्जीवेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- गौरतलब है कि झालावाड़ तथा जयपुर से श्रीगंगानगर मार्ग पर 30-30 दिवस के लिये चलाई जा रही मोबाइल वैन द्वारा जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग के लगभग 200 स्थानों पर प्रचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन वाहनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक 15 स्टैंड की मिनी प्रदर्शनी भी ले जाई जा रही है, जो स्थान-स्थान पर आम जन के लिये प्रदर्शित की जाएगी।

'हर घर नल कनेक्शन'

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेग्यूलर विंग एवं मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 203.83 करोड़ रुपए की लागत से 145 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इससे 173 गाँवों में 38503 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे। इसके अलावा बैठक में मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में सर्वे और डीपीआर तैयार करने के दो कार्यों के लिये 268.60 लाख रुपए के प्रस्ताव तथा जेजेएम की वार्षिक योजना के तहत सपोर्ट गतिविधियों हेतु 297.55 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।
- बैठक में रेग्यूलर विंग के तहत धौलपुर के 36 गाँवों के लिये 47 करोड़ रुपए की लागत से 29 ग्रामीण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इससे 9673 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे।
- झालावाड़ में 34 गाँवों के लिये 24.49 करोड़ रुपए की लागत से 31 ग्रामीण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इससे 6008 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे।

नोट :

- करौली में 43 गाँवों के लिये 41.80 करोड़ रुपए की लागत से 36 ग्रामीण योजनाओं की स्वीकृति दी गई, इससे 9274 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे।
- बूंदी ज़िले में एक ग्रामीण परियोजना में 'हर घर नल कनेक्शन' के लिये 2.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई।
- इसके अलावा अलवर में 46 गाँवों के लिये 54.10 करोड़ रुपए की लागत से 47 ग्रामीण योजनाओं की स्वीकृति दी गई, इससे 11859 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे।
- बृहद् पेयजल परियोजनाओं के तहत बारां ज़िले में सिंगोला एनिकट आधारित पेयजल परियोजना के लिये 34.10 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई। इसमें 10 गाँवों में 1367 'हर घर नल कनेक्शन' दिये जाएंगे।
- सर्वे और डीपीआर तैयार कराने के कार्यों में चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी आधारित पेयजल परियोजना से 265 गाँवों में 36254 'हर घर नल कनेक्शन' के लिये 156.32 लाख रुपए दिये गए। उदयपुर में सोम कमला अंबा बांध से 164 गाँवों में 26041 'हर घर नल कनेक्शन' हेतु 112.28 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।

MyBookLo ऐप

चर्चा में क्यों ?

- 28 अगस्त, 2021 को राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिये जयपुर में डिजिटल लाइब्रेरी MyBookLo ऐप का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऐप के माध्यम से छात्र-छात्राएँ अपने पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके तहत विद्यार्थियों को अलग-अलग श्रेणियों की कोचिंग दी जाएगी।
- कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से किया गया यह नवाचार आने वाले समय में राजस्थान की उच्च शिक्षण व्यवस्था को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा।
- कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं MyBookLo कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत विकसित यह ऐप कॉलेज विद्यार्थियों के लिये एक डिजिटल लाइब्रेरी होगा। जिसके माध्यम से ये वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।

नाथद्वारा में हेलिकॉप्टर जॉयराइड

चर्चा में क्यों ?

- 28 अगस्त, 2021 को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने राजसमंद ज़िले के नाथद्वारा में हेलिकॉप्टर जॉयराइड का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई ऊँचाईयाँ प्रदान की जाएंगी और सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयासों से क्षेत्र में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
- जोशी ने कहा कि नाथद्वारा आने वाले पर्यटकों को उदयपुर-नाथद्वारा-कुंभलगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य को हेलिकॉप्टर के माध्यम से निहारने का मौका मिलेगा तथा वह एक दिन की बजाय दो-तीन दिन नाथद्वारा में रुककर पर्यटन का आनंद ले सकेंगे, जिससे क्षेत्र के पर्यटन विकास सहित यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी संभव हो सकेगा।
- उन्होंने कहा कि यात्रीभार को देखते हुए हेलिकॉप्टर की संख्या में भी इजाफा किया जा सकेगा और आगामी दिनों में दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर का उपयोग भी किया जाएगा।

नोट :

पैरालंपिक में स्वर्णिम सफलता

चर्चा में क्यों ?

- टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में 30 अगस्त, 2021 को राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई। शूटिंग में अवनि लाखेरा ने गोल्ड मेडल, भालाफेंक (javelin throw) में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर निवासी अवनि लाखेरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास एसएच-1 के फाइनल में 249 पॉइंट्स स्कोर कर गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला एथलीट हैं।
- भालाफेंक प्रतियोगिता में राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.1 मीटर दूर भाला फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उल्लेखनीय है कि झाझरिया इससे पूर्व पैरालंपिक में दो बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।
- गौरतलब है कि शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनि लाखेरा राजस्थान वन विभाग में बतौर एसीएफ कार्यरत् हैं। देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर भी वन विभाग में एसीएफ के पद पर कार्यरत् हैं।

टोक्यो पैरालंपिक खेल में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिये पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 30 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके लिये पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य सरकार स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः तीन, दो तथा एक करोड़ रुपए की राशि देगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता शूटर सुश्री अवनि लाखेरा को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर सुंदर गुर्जर को एक करोड़ रुपए इनामी राशि दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने जीवटता की मिसाल कायम करते हुए देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है।
  - प्रदेश की अन्य खेल प्रतिभाओं को भी उनकी इस उपलब्धि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली इनामी राशि 75 लाख, 50 लाख तथा 30 लाख रुपए को वर्ष 2020-21 के बजट में बढ़ाकर क्रमशः 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तथा 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी।
- इसी तरह एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ाकर क्रमशः 1 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए एवं 30 लाख रुपए करने की भी उन्होंने बजट में घोषणा की थी।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्तियाँ दी जा रही हैं।
  - टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले तीनों खिलाड़ी अवनि लाखेरा, देवेंद्र झाझरिया तथा सुंदर गुर्जर को राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न आधार पर वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की है।

नोट :